[Shri Vidya Charan Shukla]

and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1970-71, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : Now the question is :

"That clauses 2, 3, the Schedule, clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I beg to move :

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

16.49 hrs.

GENERAL BUDGET, 1971-72 —GENERAL DISCUSSION

MR. CHAIRMAN : Now we take up the General Discussion on the Budget 1971-72.

AN HON. MEMBER : There are only ten minutes to 5. We may have the discussion tomorrow, Sir.

MR. CHAIRMAN : There is still one hour left.

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, हमने जो कट मोशन्स दिये हैं, उन का क्या होगा ?

MR. CHAIRMAN : There is no question of cut motions so far as the General Discussion is concerned. Those who want to speak may speak.

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : सभापति महोदय, अभी हाल में जो इलेक्शन हुआ, उसमें खास तौर से दो बातों का वादा किया गया : एक, अनएम्पलायमेंट की प्राबलम को साल्व करेंगे और दूसरे, देश की गरीबी को दूर करेंगे। ये दोनों सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। वित्त मन्त्री ने जो बजट हमारे सामने रखा है, उसमें भी उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया है।

सबसे बड़ा सवाल है अनएम्पलायमेंट की समस्या को साल्व करने का। जमीन के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसकी हदबन्दी होनी चाहिए। यह भी एक रास्ता है, जिससे देश में बेकारी दूर हो सकती है। लेकिन मैं यह कभी नहीं समझता हूं कि बेकारी को दूर करने के लिए जमीन की हदबन्दी ही सबसे बड़ा उपाय है। इससे थोड़ी बहुत सहायता जरूर मिल सकती है। लेकिन जब तक देश में इंडस्ट्रीज न बढ़ें, चाहे वे लार्ज-स्केल हों, या स्माल-स्केल या मीडियम स्केल, तब तक देश में अनएम्पलायमेंट का सवाल खत्म नहीं हो सकता है। हमने एक पालिसी ली है और वह पालिसी है हमारी मिक्स्ड एकोनामी की। यहां जितने लोग बैठे हुए हैं विपक्ष के जो अपने को कम्युनिस्ट कहते हैं या दूसरी पार्टियों के कहते हैं या हमारे अन्दर भी जो लोग इस पक्ष में बैठे हैं और सरकार भी इस बात को बहुत जोर से कहती है कि पब्लिक सेक्टर को बढ़ाया जाय, पब्लिक सेक्टर की आवाज बहुत उठायी जाती है। एक बात मैं कह दूं कि जब किसी मसले का साल्यूशन न हो तो दो तीन बातें आम तौर पर कह दी जाती हैं। एक तो पब्लिक सेक्टर का नाम ले लिया जाता है। एक कारपोरेशन बना दीजिए, यह कह दिया जाता है। और तीसरे कमीशन का नाम ले लिया जाता है कि कमीशन बैठा

दीजिए । कमीशन की हालत हम जानते हैं। जो कमिशन बैठते हैं और उनकी जो रेकमेंडेशंस होती हैं, उन रेकमेंडेशंस में सालों लग जाते है और तब तक फिर चुनाव आ जाता है। तो उसकी हालत हम जानते हैं। दूसरी बात कही जाती है कि पब्लिक सेक्टर में सारी इंडस्ट्री डाल दी जाय। लेकिन हमारा अनुभव यह है, मिसाल के लिए एक ही बात हम लेते है और वह है हमारी दुर्गापुर की जो पब्लिक अन्डर-टेकिंग है उसकी बात। पब्लिक अण्डरटेकिंग में हम अब तक कितना घाटा दे चुके हैं इसका कोई हिसाब इस सरकार ने नही दिया। लोग कहते हैं कि हम साल में 22-24 करोड़ रुपया उसका घाटा देते हैं। अभी तक जो खबर हमें मिली है उसके अनुसार 160 करोड़ रुपये का घाटा हम दे चुके है और अभी भी जो वहा स्ट्राइक वगैरह चल रही है उससे जो घाटा उठाना पड़ रहा है उसका कोई हिसाब नही है। इस तरह वहां की इंडस्ट्री दुर्गापुर की पब्लिक सेक्टर में होते हुए ठीक तरह से नही चल रही है तो मेरी समझ में यह बात नही आती कि कैसे यह बात कही जाती है कि सारी इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर मे डाल दिया जाय। दूसरी भी कई इंडस्ट्रीज है पब्लिक सेक्टर में, उनको ले लीजिए। उनमे भी हम घाटा दे रहे है। रेलवे को ले लीजिये। रेलवे की यह परम्परा रही है कि रेलवे में सबसे ज्यादा रुपया, कई हजार करोड़ रुपया हमने लगा कर रखा हुआ है और वह बराबर जनरल बजट में उससे रेलवे कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रही थी। लेकिन अभी जो हमारा बजट आया रेलवे का उसमें 50 करोड़ रुपये के घाटे का अनुमान भरा हुआ है। ...(व्यवधान)... अभी हमारे एक दोस्त ने कहा कि चोर भरे हुए हैं। तो यह लोग उन्हीं चोरों को सपोर्ट कर रहे है। पता नहीं आम जनता ही यहां की चोर हैं या सरकारी नौकर चोर हैं या लेबर यूनियनें जिन को सपोर्ट करती है वह चोर हैं, इसका पता तो वह लगाएं। लेकिन कुछ भी हो, चोरी हो या न हो, यह बात जरूर है कि रेलवे जो हमारी इतनी बड़ी पब्लिक सेक्टर की अन्डरटेकिंग है उसमें घाटा चले यह बात कुछ हमारी समझ में नहीं आती है।

एक माननीय सदस्य : रेलवे बोर्ड को तोड़िये।

श्री क० ना० तिवारी : अगर रेलवे बोर्ड के तोड़ देने से घाटा पूरा होता हो तो जरूर तोड़ दीजिये। पर दुर्गापुर में क्या किया जाये? यहा तो रेलवे बोर्ड को तोड़ दिया जाये पर दुर्गापुर मे क्या किया जाये? उसका कोई सुझाव भी सदस्य महोदय दे देते तो बड़ा अच्छा था। तो हमारा ख्याल है कि इस पचड़े में न पड़ करके कि पब्लिक सेक्टर में है, या प्राइवेट सेक्टर में है जो सेक्टर अच्छी तरह से कार्य करे उसको करने दिया जाये। प्राइवेट सेक्टर खराब तरीके से काम करता है तो उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले और जो इंडस्ट्री चले वह मुनाफे में चले, घाटे के साथ मे कोई इंडस्ट्री न चलायी जाये।

श्री इसहाक सम्भली (अमरोहा) : प्राइवेट सेक्टर में कितना घाटा होता हैं? कितनी प्राइवेट सेक्टर की कम्पनियां लिक्विडेट हो गई इसको क्यों भूल जाते है?

श्री क० ना० तिवारी : आप नोट करके रखिये, जब आप का मौका आये तो जवाब दीजिएगा।

हमारा कहना यह है कि जितनी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में घाटे हो रहें हैं उनको मजबूत हाथ से डील कीजिए। यह जो यहां बैठे हुये हैं कम्युनिस्ट लोग या लेबर यूनियन के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी और लेबर यूनियनें दुनिया के बहुत से हिस्सों में काम करती हैं, रशिया में हैं, चाइना में हैं, जेकोस्लोवाकिया में हैं, ईस्टर्न जर्मनी में है, लेकिन कहां स्ट्राइक होती है वहां? अगर वहां स्ट्राइक को बर्दाश्त नहीं किया जाता

[श्री क० ना० तिवारी]

तो इस सरकार को भी स्ट्राइक पब्लिक सेक्टर में हो तो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और एक मजबूत हाथ से उसको डील करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर में भी जहां तक मजदूरों के हित का सवाल है, जहां तक उनको सुविधायें देने का सवाल है, उनको हर तरह की सुविधायें दी जायें, लेकिन यह न किया जाए कि पब्लिक सैक्टर में भी इस तरह की स्ट्राइक्स को बरदाश्त किया जाए। सरकार ने अगर इस बात को ज्यादा दिनों तक बरदाश्त किया तो सरकार यह जो कहती है कि अनएम्पलायमेंट की समस्या हल होगी, वह हल होने वाली नही है...

श्री इसहाक सम्भली : क्या मजदूर पेट पर पत्थर बांधे।

श्री क० ना० तिवारी : पत्थर बान्धे, लोहा बान्धे, कपड़ा बान्धे, आप जो चाहे बंधवा लीजिये। इसलिए इसमें एक सुझाव यह है कि लेबर-लाज में काफी परिवर्तन करने की जरूरत है और पब्लिक सैक्टर में मजबूती से उनके साथ निबटा जाए।

आज बंगाल की जो हालत है, वह आपके सामने हैं अभी हमारे एक मित्र—भट्टाचार्य जी बोल रहे थे। वह कह रहे थे कि उनके आदमी मारे जाते हैं, कांग्रेस के मारे जाते हैं, इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि अगर अजय मुखर्जी को वहां का चीफ मिनिस्टर बना देंगे तो वहां की हालत नहीं सुधरेगी। इन लोगों का एक ही मनसूबा है कि वहां की सरकार इनके हाथ में रहे, तब तो वहां की हालत सुधर सकती है, वरना नहीं सुधरेगी। जिसका नमूना अभी हम ने देख लिया है—जिस वक्त वहां कम्युनिस्ट हुकूमत थी, उस कम्युनिस्ट सरकार के बाद जो वहां हालत हुई और उसके बाद जिस तरह सरकार वहां टूटी और उस वक्त से जो गड़बड़ वहां चली, वह आज भी चली आ रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है—ये लोग जिम्मेदार हैं।

मैं इस सरकार से एक दूसरी बात कहना चाहता हूं—या तो आप शासन कीजिये, वरना किसी को सौंप दीजिये, जिसके भाग्य में होगा वह लेकर चलावे, लेकिन आप मजबूती के साथ कदम उठावे। अब आप के पास ताकत आ गई है, जनता ने आपको मेंडेट दिया कि आप बीच का रास्ता अख्तियार करें और जिस तरह से हो इस देश की इंडस्ट्रीज को बढ़ावे। इसके लिए आप मजबूत कदम उठावें। इसलिए मेरा निवेदन है कि पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर—मैं पब्लिक सैक्टर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि आइ०सी०एस० और आइ०ए०एस० आफिसर ही इसको मैनेज करें। जितने टैकनीशियन्ज़ है, उनको ट्रेनिंग दे कर, उनके हाथ में काम सौपिये, जिससे वे इन का मैनेजमेंट अच्छी तरह से चला सकें। आप उनका एक कैडर तैयार कीजिये, जो आप की इंडस्ट्रीज को मैनेज करे। लेकिन आप केवल आइ०एस०एस० या आइ०सी०एस० आफिसर्ज के हाथ में इन कामों को रखते है, जिन को बिजनेस का कोइ एक्सपीरियेन्स नही है। वे इन के मालिक बन जाते हैं, ऐसी स्थिति मे आपकी की इंडस्ट्रीज कहां तक अच्छी तरह से चलेंगी यह बात समझ में नहीं आती है।

17 hrs.

दूसरी बात जमीन के बटवारे के बारे में कही गई है—हमारे माल मन्त्री ने भी उसका उत्तर दिया है और मैं भी उनके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन एक बात के खिलाफ जरूर हूं—फैमिली यूनिट नही होना चाहिए, इन्डिविजुअल यूनिट होना चाहिए। आज आपके यहां हर चीज मंहगी है। एक बच्चे को पढ़ाना होता है

तो उस की स्कूल की फीस देनी पड़ती है, किताबों की कीमत देनी पड़ती है, रेलवे का ट्रैवलिंग का खर्च है, सब की सब चीजें मंहगी हैं। आप के जितने कन्ज्यूमर गुड्स हैं, सब मंहगे हैं। ऐसी हालत में थोड़ी बहुत आमदनी उनको हो जाती है, लेकिन उसमें अगर आप इकानामिक यूनिट नही रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हम अनएम्पलायमेंट को कहां तक सोल्व कर सकेंगे, इस से तो अन-एम्पलायमेंट बढ़ेगी। जिनके पास दो हजार, एक हजार, पांच सौ या 200 एकड़ जमीन है, उसको कम कीजिये लेकिन उनके पास एक इकानामिक यूनिट होना चाहिए। परिवार को यूनिट न मान कर, उसकी फैमिली के हर बच्चे को यूनिट मान कर उसको तय किया जाये। मान लीजिए आपके तीन बच्चे है उनमें एक बालिग है और दो नाबालिग है उनमें जो बालिग है वह तो कही कमाकर खाता है अगर उसे एम्पलायमेंट मिला हुआ है वरना वह भी अपने मा बाप के ऊपर भार बना रहता है। और जो दो बच्चे नाबालिग है, दस पांच साल के बाद ही वह बालिग होंगे लेकिन इस बीच मे वे क्या खायेंगे? या तो फिर आप एक बात कर लीजिए जिसके फेवर मे मैं भी हूं। चाहे कोई दुकान करे, खेती करे या नौकरी करे, लेकिन सभी का एक ही मकसद रहता है कि उनका पेट भरे, उनको कपड़ा मिले, बच्चो को शिक्षा मिले, उनकी दवादारू हो और वे अच्छी तरह से रह सकें। हर एक वाक आफ लाइफ में लोग इसी के लिए काम धन्धा करते हैं। अगर सरकार में इतनी ताकत है, ऐसा कलेजा सरकार का है तो एक बात वह जरूर करे कि जितने हमारे असेट्स हैं वह सब ले लिए जाये, एक एक इंच जमीन ले ली जाये, सारे कल कारखाने ले लिए जायें, सारी चीजें ले ली जायें लेकिन मेहरबानी करके हमारी सारी लायबिलिटीज भी आप ले लीजिये। हमारे बच्चो की शिक्षा, दवादारू, खाने-कपड़े और एम्पलायमेंट की सारी जिम्मेवारी भी सरकार अपने ऊपर ले। अगर यह बात हो जाये तो फिर कोई भी आपत्ति की बात नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार का दिमाग इस बात में बिलकुल साफ होना चाहिए। अगर समाजवाद के माने यह हों कि एक व्यक्ति जिस का पेट भर रहा है उसका पेट खाली रखा जाये तो ऐसे समाजवाद से हम इनकार करते हैं। हम तो समाजवाद के माने या समझते हैं कि जिसका पेट भरता है उसका पेट भरे, जो कपड़ा पहनता है वह कपड़ा पहने लेकिन साथ ही जिसका पेट खाली हैं उसका भी पेट भरा जाये, उसके लिए कपड़े का प्रबन्ध हो और उसके लिए रहने का मकान बनाया जाये। जिन लोगों को कुछ सुविधायें मिली हुई हैं वह तो एक हद तक बनी रहें और बाकी जिनके पास सुविधाये नही हैं उनको भी वह सुविधायें मिले।

अभी आपने कोई टैक्स नही लगाया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आगे भी आप टैक्स नही लगायेंगे। लेकिन मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और जिसका कि बड़ा भय है। पंजाब ने दूसरा तरीका अख्तियार किया है कि जितने भी कर किसानों पर थे वे सब हटा दिए गए हैं। लेकिन मैं समझता हूं इंडस्ट्रियलिस्ट्स की तरफ से इस बात की मांग ज्यादा हो रही है और सरकार के दिमाग में भी यह हैं कि किसानों की हालत बहुत अच्छी हो गई है इसलिये उन पर इनकम टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स और हर तरह के टैक्स लगाये जाने चाहिएं। मेरा ख्याल है कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। अभी चुनाव में हमने लोगों से यह वायदा किया हैं कि जिनकी माली हालत अच्छी नहीं है उन की माली हालत अच्छी बनायेंगे लेकिन जिनके पास एकोनामिक यूनिट की जमीन है वह उन्हीं के पास रहेगी। अब यदि आप ऐसा कुछ करते हैं तो हम अपने वायदे के विपरीत जायेंगे। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह इस

[श्री क० ना० तिवारी]

प्रकार का कोई कर लगाने की बात न सोचे। आप के जो कर्मचारी है, बड़े-बड़े अफसर है वह चार हजार या तीन हजार तनख्वाह लेते है तो इस तरह से समाजवाद नही आता। यहा पर लोग कहते है और अभी कल यहा पर कालिंग अटेंशन भी था इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की हड़ताल के सम्बन्ध में, हम सुनते हैं कि वहां पर आपके आफिसर्स वेलपेड है लेकिन फिर भी दिन रात यही डिमाण्ड की जाती है कि तनख्वाह बढाओ। मजदूरों की मजदूरी बढे इसपर हमे कोई एतराज नही है, उनकी माली हालत सुधरनी चाहिए लेकिन साथ ही साथ हम इस बात के पक्ष मे भी है कि किसानो के जो लडके है, जोकि देहात से आते है, उनकी माली हालत भी बिगडने न दी जाये। देहातो मे हमारी जो माली हालत है उसको खराब होने न दिया जाये। हमारे वित्त मन्त्री भी एक किसान है, वे भी किसान परिवार से आते है इसलिए वे हमारी डिफीकल्टीज को भी समझते हैं। वे अपने अफसरो के दबाव मे आकर या इस साइड के दबाव मे आकर इस तरह का गलत कदम कभी नहीं उठायेंगे जिससे कि देहात के लोगो को परेशानी हो।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (ग्वालियर). बड़े किसानो के बारे मे आपकी क्या राय है?

श्री क० ना० तिवारी हमारी राय यह है कि हर आदमी के पास एकोनामिक यूनिट रहनी चाहिए और वह इंडिवीजुअल यूनिट होनी चाहिए, हम परिवार को यूनिट नही मानते है। यह हमारा निजी विचार है। बडे किसानो के पास अगर ज्यादा जमीन है तो उसको कम करना चाहिए।

इसलिए दो बातो की ओर मै वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरी समझ मे आपने जो नमक पर से टैक्स हटा दिया है तो वह बहुत अच्छा काम किया है और वैसा करके गाधी जी के स्वप्न को पूरा किया है। लेकिन ठीक उसी तरीके से सारे स्वप्न जोकि किसानो के हैं उनको बड़ा धक्का लगेगा अगर उन पर इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेज, इनडाइरैक्ट टैक्सेज जोकि हर तरह के पे करते है, 51 परसेंट इकम हम किसान लोग देते हैं, फिर भी उनके ऊपर टैक्स का भार और बढा दिया जाय जिसके बोझ से वह इतने लद जाय कि जो आज उनकी माली हालत है वह खराब हो जाय तो यह एक अच्छी बात नही होगी। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आगे जो भी बजट आप बनाये उसमे किसानो का सब से ज्यादा ख्याल रखे।

देश मे से बेकारी की समस्या को हल करने का एक ही तरीका यह न समझा जाय कि जमीन का बटवारा कर दिया जाय। खाली जमीन का बटवारा कर देने से बेकारी का सवाल हल हो जायेगा इस बात को दिल से निकाल दीजिये।

जहा तक प्राइवेट या पब्लिक सैक्टर का सवाल है जाहिर है कि पब्लिक सैक्टर अगर अच्छा काम करता है तो उसे आप तरजीह दीजिये और उस मे आप रुपया लगाइये लेकिन मेरा कहना है कि अगर कही पर प्राइवेट सैक्टर अच्छा काम करता है तो उसे भी आप प्रोत्साहन दीजिये। मैं समझता हू कि बहुत से लोग मेरे इस विचार मे सहमत नही होंगे कि प्राइवेट सैक्टर की इन्डस्ट्रीज को भी हमे प्रोत्साहन देना चाहिए और बढाना चाहिये लेकिन पब्लिक सैक्टर की कुछ जगहो पर जो हम हालत देख रहे है और रेलवे और दुर्गापुर की जो दो मिसाले मैने सदन के सामने रखी है अगर अब यही हालत पब्लिक सैक्टर की रहेगी तो इस तरह से अनएम्पलायमेंट सोल्व करने का जो एक स्वप्न हम लोग देख रहे हैं वह हमारा स्वप्न पूरा नही हो सकेगा।

SHRI SAROJ MUKERJEE (Katwa) : At the very outset, on behalf of the Communist Party of India (Marxist) I oppose, the basic policies from which the Budget provision and various items of the budget placed here emanate, because the basic policy of the Government of India today as expressed in the Budget is to develop a capitalist economy, and a capitalist economy is a crisis-ridden economy. The leaders of the Congress Party including Mrs. Gandhi profess day and night that they are building socialism in India, but there is not a single element of socialism in the Budget. The main principle of the Budget is to see that the rich become richer and the poor become poorer. This is the main policy on which everything emanates. This is why the Indian economy is on the verge of ruination today, and on this crisis-ridden economy the hon. Finance Minister expects the development of various aspects of the country's economy and he is exploring the possibility of a growing economy. He has painted a rosy picture of the last one year. He has said that they G. O. I. have done many things and that they will do many more things in future, but actually the picture is quite contrary. We have seen that at least for the last one year unemployment has grown, factories have been closed and deficit Budget is continuing.

He has put before us an over-all deficit of Rs. 240 crores in this interim Budget. This is not all. He has said that there will be increased Reserve Bank credit, but we know that without adequate resources if the bank credit is increased, there will be further deficit.

Therefore the real deficit will be much more than Rs. 240 crores which means more inflation and soaring prices. The price of essential commodities, barring one or two, is soaring up every day. People throught out India are suffering because of the rise in prices. The Finance Minister said that they have not taxed the people this time but they have in mind to take into account the mainstay, *i.e.*, the power to raise more resources. That means that in the Budget which will be presented in May there will be taxation proposals. People will be taxed. You cannot get resources outside the plan. Only by taxation you will have to raise the resources. We have seen that during the last 23 years they have been taxing the poor and not the rich. Whatever taxes have been put on the rich have sometime been evaded, and at other times they had been exempted. That seems to be their main policy.

He has rebuked the State Governments and blamed them for their increasing over, drafts on the Reserve Bank. He has put the responsibility on them. We say that the State Governments are not responsible for this. It is the fiscal policy of the Central Government which puts the State Governments in this plight. The price policy and the fiscal policy of the Central Government compel the State Governments to run into deficit and their economic position also deteriorates. This way, the economic position of India is fast deteriorating. That is why our party has demanded, we demand—even now in the Lok Sabha and outside also that the States must have more power, that they must have 75 per cent of the revenues collected by the Centre in that State. I mean 75 per cent of the Central taxes such as the Corporation Tax, Income Tax etc. which are collected in that State and the balance of 25 per cent will remain with the Centre. The Constitution should be amended to give effect this proposal. If the Central Government is keen on the development of the State they can do this because they have got two thirds majority and they can change Constitution so that the States can be placed in a better financial position. 25 per cent of the Central revenues are enough for the Central Government to discharge their responsibility regarding defence, foreign affairs, communications etc.

No new policy has been enunciated in the Budget. The old policy continues. He has painted a rosy picture, the real position has not been stated by him. Take for example unemployment. We have got a back log of 78 million unemployed. Annually 50 lakhs of persons are added to this number. The hon. Minister said that their aim was to provide employment to atleast one person per family and that they have already sanctioned Rs. 50 crores for this purpose. This a fantastic proposal. There are 11 crores of families in India and if you give employment to one man per family, how long it will take to cover all the unemployed ? Moreover factories are closed ; number of retrenched works and employees are increasing day by day. For example,

[Shri Saroj Mukerjee]

in West Bengal, there were 200 factories closed during the UF regime. The UF regime helped to open 39 factories. But during the one year's President's rule, the total number of closed mills and factories has risen to 400. Similarly in Andhra, Kerala, Punjab, Delhi, Bombay, everywhere, the factories are getting closed. What has been the result ? The result has been that millions of workers are without jobs ; their families are on the verge of ruin faced with starvation and hunger. To remedy this, nothing is being done.

It was said that we are getting towards developing economy. No. That is not the the sign of a developing economy. It is a retrograde economy. The workers are on the verge of ruin. The unemployed are not getting jobs. Millions of people are getting unemployed day by day. Their policy is utterances of sweet words, nice talks and so on, on the one hand. And on the other of repressing the people. Sweet words, very nice words, are uttered by our Prime Minister.

AN HON. MEMBER : Vote-catching.

SHRI SAROJ MUKERJEE : Not vote-catching. They want to bluff the people. Our Chavanji,, Shrimati Indiraji—they are all uttering sweet words, very nice words, but when the people fight for their employment, when the people fight for their rights they repress them. You will then see her "Rakshasi Murti", as we see in Bengal. The Prime Minister is playing there the role of a demoness ; the military, the CRP and the BSF are there. Do they think that Bengal is a colony of the Government of India ? Military rule is there. Why ? For nearly two months, military rule is there. Still, they are not able to maintain law and order. Vice-Chancellors and other respected leaders are being killed, but no enquiry is being made. The Local people say "we have seen who are the killers but for fear of life we cannot telll their names." Because higher police officers and others are in league with goondas, murderers and assassins. There is a big high-level conspiracy ; high-level plotters are there. They are doing this, the killing of comrades. It is with a heavy heart that we have come here. We have lost 230 comrades of our party during the President's rule. The other parties members, youths and general people, are also being killed ; this number is nearly a hundred. All this is killing designed by high-level conspirators who are league with the Government of India.

Therefore, we say that during the President's rule law and order has very much deteriorated. It is not being maintained anywhere. The people are always panicky ; always living in fear of being assassinated and all that. On the one hand, they are uttering sweet words and, on the other, when the people fight for their rights, they give them bullets. They are killing them. Terrible repression is there. That is why we demand that when you pass the budget, you must assure us that military is withdrawn immediately ; that the CRP is withdrawn from West Bengal immediately. Why Bengal only ? Kerala, Andhra, every-where—they would not tolerate this. Even after the election in Miryalguden, in the Telengana area of Andhra Pradesh, where our representative has been elected, the zamindars have killed two or three kisans there. 40 persons in Kerala have been killed by the armed forces. Therefore, we say that the writting on the wall must be read. The Government of India, the present leaders, should read it.

With the military for 16 years, East Pakistan was being ruled but the people threw out the military rule and stood on their own legs. By the strength of the military, the British regime could not curb or suppress us. The Congress regime sometimes could not suppress us. But Shrimati Indira Gandhi's Government, Chavanji's, Government, now wants to do the same and through military and the CRP they want to suppress the democratic movement. Really, they are suppressing democracy.

Where the people are fighting for their democratic rights, they are sending the military. Why ? Why are they afraid of the people ? You see they are not functioning even the Parliamentary Democracy. There, in West Bengal, through an election the ULF has got a majority. 123 members belong to the ULF. The normal procedure should have been that the leader of that front, Shri Jyoti Basu, should have been called. Had he failed to form a Government, Shri Bijoy

Singh Nahar, of the second biggest party should have been called. People should see that parliamentary democracy is functioning. But instead of doing that, they are conspiring with Muslim League and others, acting from behind the scenes and pulling strings and all that. Now, they are combining all sorts of forces—the CPI, other erstwhile leftists, the Muslim League and so on,—so that the real representatives of the people who are really in a majority cannot come to power.

In other States, this is not done. When there is hope or expectation that the ruling Congress may rule, they call their men even if they are in a minority, as we have seen in Bihar and Orissa. This is not the real functioning of parliamentary democracy.

Our demand will be, open factories and give credit to small and middle factory-owners. That is not being done. Mr. Chavan said in the budget speech that credit supply is increasing and many new branches have been opened for issuing credit. But he has not mentioned to whom credit is paid, whether it is paid to millionaires or to poor peasants and poor and middle factory-owners. So far as we know, not a single poor factory-owner or small and middle factory-owner or poor peasant has got any credit facilities after bank nationalisation. We supported bank nationalisation because it was a progressive measure. But after that, they ought to have taken some measures. But they have not done it. During the past seven months, they have not done anything. This is why I say only nationalisation of banks will not do. Credit should be given to the smaller and middle factory-owners, poor and middle peasants and to cottage industries. As you know, four million families depend on the handloom industry, but throughout India, the handloom industry is on the brink of disaster. No small-scale handloom factory has got any credit from the nationalised banks.

Another progressive measures is the abolition of privy purses. I do know why Chavanji and Indiraji never say, "We would not pay any comensation. We have got a huge majority. We will change the Constitution and delete the provision for payment of compensation." For so many long years, they have been getting Rs. 5 crores every year. Now you want to give 20 times that amount—Rs. 100 crores—to the princes by way of compensation. If Rs. 100 crores are kept as a fixed deposit in a bank, they will get Rs. 8 crores per year, instead of Rs. 5 crores they are now getting! What a fantastic progressive measure they have taken! They should announce, "We will change the provisions of the Constitution. We will not give any compensation."

Then, why should there be an increase of Rs. 65 crores in the defence budget? India has got a glorious anti-imperialist tradition. We do not know who is going to wage a war against us. What is the use of increasing defence expenditure? In the *Economic Times* of 27th or 28th February, we saw a small news item that from the State-owned fertiliser factory in Kerala, Government of India has sent fertilisers to South Vietnam for a few thousand dollars. India has got a glorious anti-imperialist tradition. Why should we help South Vietnam against North Vietnam by sending them fertilisers for just a few thousand dollars? We must condemn this. If this is not a fact, our leaders must say that this is not a fact. But the news has appeared in the *Economic Times*. We do not know why defence expenditure should be increased. We do not know why we should help South Vietnam, when we have no trading with North Vietnam. India has got a glorious anti-imperialist tradition. You are besmearing our glorious past by doing these things. We think that with all these policies, you cannot improve our economy. The whole thing should be changed basically. We tell our Government that unless and until the basic policy is changed, nothing can be done and our economy cannot be improved.

SHRI M. B. RANA (Broach): Sir, I rise to support the budget presented by the hon. Finance Minister. To quote his own words:

> "Our task now is to reassess the entire range of our policies so as to give them a sharp focus of effectiveness, to translate these policies into concrete programmes of action and to implement these programmes with speed and determination. Only so can we accelerate the process of growth, reduce dis-

[Shri M. B. Rana]

parties in income, wealth and economic power, generate employment on a massive scale and avoid pressures on prices or balance of payments of the kind which generate internal tensions and increase our dependence on external credits."

I hope and pray that our next budget also will be of the same type in May and there will be no tax proposals for anyone of us.

The main problem before us is employment. Quoting his own speech .

> "By far the most urgent problem that needs our whole-hearted attention is the problem of unemployment ..There can be no question that poverty and unemployment cannot be eradicated without a sustained process of growth. But there are several ways of achieving growth ; and we have to seek out these which make the maximum impact on unemployment and mass poverty."

Most probably it is the mental attitude of the people of India which is responsible to some extent for unemployment here. Usually in India there is one bread-earner in the house and there are five or six dependents of that bread-earner. In UK and other advanced countries everyone who is above the age of eighteen tries to make a living. If we change our attitude on that basis I am sure we shall get much more employment.

Government are doing their best to remove or at least reduce unemployment. Public Sector Undertaking is an institution which is created mostly to get rid of unemployment. They employ a large number af people even at the cost of making losses, as mentioned by our colleague, Shri Tiwari. Even though they incur losses, they help to a large extent in solving the problem of unemployment. While I was the Chairman of the Committee on Public Undertakings I suggested to the public undertakings that they should give greater emphasis to this aspect and that they should provide the people with land and know-how so that we can reduce unemployment.

Coming to the elections, there was a Grand Alliance of the Syndicate, the Jan Sangh and the Swatantra Party. The Grand Alliance thought they had a very glorious future before them but they ended in shame at the end of the polls. People thought that this Grand Alliance should not be given any support. Here I am reminded of the Portuguese people. As stated by Mr. Otto Rothfeld in his book, the Portuguese wanted to contest with the British Empire where the sun never sets for the supremacy in India. But they went down as a nation of cooks and musicians. This is the position of the Grand Alliance in Gujarat now. They started with the hope of capturing all the 24 seats in Gujarat. They have been able to secure only 11, losing 13. So the Grand Alliance has failed, as far as the poll in Gujarat is concerned.

They hoped to return in a vast majority in this House. They have returned only 11 from Gujarat and five from the rest of India. That is their strength. Their position is somewhere in that corner, fifth or sixth. They promised everything but they will not be able to do anything in this House in spite senior people like Shri Mishra coming to this House.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE : Is he speaking on the Budget or on the grand alliance ?

MR. CHAIRMAN : That is part of the Budget discussion.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai) : Your corpus itself is an alliance.

SHRI M. B. RANA : The Budget has put stress on the abolition of poverty and the programme for tackling the problem of unemployment and irrigation. I am glad that the problem of irrigation is tackled. In Gujarat we have a very big problem of Narmada Project which is the lifeline for the whole of Gujarat, not only of Gujarat but of Kutch and South Rajasthan. This Narmada Project has to be taken into consideration. I am glad to know that the Madhya Pradesh attitude is now gradually changing towards a compromise. It is our own Government of Gujarat which is refusing to come to any terms with the Madhya

Pradesh Government. If they come to some settlement, I am sure that problem can be solved in no time.

Then, there is the drinking water problem which has to be tackled in our parts. There are tanks in all the villages which require to be deepened. There are small rivers which require to be bunded. If these things are done, I am sure, the problem of drinking water would be solved in no time.

Besides the Narmada Project there is the flood and earthquake problem in Broach District to which I belong. We had floods in 1968, earthquake in 1969 and another flood in 1970 with the result that the whole district is now shaken up. Out of 12,000 houses in Broach nearly 9,000 are cracked up ; they are not worth living in. These problems have to be solved sooner or later.

The flood problem can be solved by small dams and by breaking the rivers. Broach was one of the biggest ports not only in India but in Asia. In the days of the Egyptian PHARAOHS the Dacca mulmul which covered the Egyptian mummies was sent through the port of Broach by international boats. But now it has silted up so much that not even small boats can come in the Broach Port. The whole coastline of Gujarat which is nearly 1,000 miles long has several possibilities of bringing up good ports. Broach and Dahej are two ports that can be developed to a great extent. If we develop these and other ports, I am sure, we shall be able to do a good deal of work for Gujarat.

There are many things which have to be tackled in time. Unemployment, irrigation and many other problems of India are there. I am sure, with the help of Government and with the help of the Opposition which, I hope, will change its attitude and not adopt a negative attitude which they used to adopt in the Fourth Lok Sabha—they have also made some promises to the electorate and they have to fulfil their promises ; by this negative attitude which they adopt towards this Government, they will not be able to fulfil their own promises—we shall be able to tackle all the problems of India very soon.

SHRI SURENDRA MOHANTY (Kendrapara) : Mr. Chairman, at the outset I should like to preface my remarks on the Budget by congratulating the Finance Minister for the massive majority which his party has obtained in the last general elections under the leadership of Shrimati Indira Gandhi. But I would only humbly submit that the Government should not gloat over this situation day in and day out. In the President's Address we had told that the Congress Party had attained a majority. In the Budget it has been repeated. I would only submit that this victory is an occasion for self-introspection, for quiet thinking and for a pledge to implement the *garibi hatao* programme which the Congress Party had given out to the masses.

Having said so, I had expected that in this Budget there would not be generalised features and vague intentions. It was expected that the Finance Minister will spell out some concrete programmes as to how he is going to implement the various assurances.

In that context, I would like to invite the attention of the House to the aspect of employment. The hon. Finance Minister has repeated an old scheme of providing Rs. 50 crores for giving employment to each wage earner in a family. The hon. Finance Minister is intelligent enough to note that Rs. 50 crores is a mere pittance, a drop in the ocean. We thought it to be a political gimmick when this employment programme had been spelt out about six months ago. This is no new programme that has been spelt out in the Budget Speech of the hon. Finance Minister. I think, long before this election, this programme had been spelt out as an immediate measure, as an urgent measure, to tackle the unemployment problem.

Now, this Rs. 50 crores programme is going to spread over 4000 blocks with the target of providing Rs. 100 per month to every wage earner in a family. We had expected that the Government of India should have in the meantime identified the districts, identified the blocks, in which the programme is going to be implemented. But what I understand from the Budget Speech of the hon. Finance Minister is that the State Government have been asked to formulate the schemes. Now this will go on between the Government of India and the State Governments. If I am not pessimistic enough, it is going to be in the doldrums. Even out of

[Shri Surendra Mohanty]

this amount of Rs. 50 crores, according to my reckoning, at least one-third will go towards the administrative cost. If Rs. 16 crores are earmarked for the administrative cost alone, the only persons who will benefit under this employment scheme is either a Secretary or a Deputy Secretary and hordes of other administration staff, and not the poor rural people for whom this programme is ostensibly meant.

We were told that there were special development schemes for 45 districts. This was another the schemes which had been spelt out by the Government of India to urgently tackle the development problem in the rural areas. These development agencies which will address themselves to the aspect of agriculture, irrigation, etc. are nothing new. They were there in the Plans and it was for the Finance Minister to have made an honest assessment of the situation and to have told us how these development agencies or, as a matter of fact, for that this Rs. 50 crores schemes is going to mitigate the hardships in the rural sector.

I would like to invite the attention of this House to another aspect of the matter. It is not the unemployment problem in the rural sector that is so much facing us. But what is staring at us today is the problem of unemployment in the urban sector. It has been fashionable of late to say that unemployment is not confined to urban sector alone. There is a refusal to recognise the agonies of the educated unemployed. With all humility, I would submit that uneducated person is never unemployed.

Suppose a man runs a tea shop or a pan shop. He engages five other persons and a cultivator who is uneducated maintains a whole family. But that is not the case in the case of the educated unemployed.

According to published figures, till October 1970 we had educated unemployed in this country to the order of about 4 million. It is surprising that a responsible Government headed by Mr. Chavan and a socialist like Shrimati Indira Gandhi should have remained silent over the problem of educated unemployed. With all emphasis at my command, I would like to submit that unemployment of a growing population is the greatest danger to a socialist democracy that we profess to bring about through the ballot box.

Sir, there is another aspect to which I would like to invite the attention of this House. The Finance Minister has sought to assure us that the price situation in the country is registering downward trend. If I remember correctly, according to him, though the price index has registered an upward trend in the case of manufactured articles and the cost of living index has gone up, the food prices have gone down to the order of 6 to 7 per cent. While it may be true of wheat, I should inform the Finance Minister that the case is exactly the opposite in the case of rice. Sir, I come from a rice-growing and rice-eating area and I tell you that the rice price has gone up fantastically high in spite of the green Revolution about which the Government is boasting so much. Having said so, I would urge upon the Government to build up enough buffer rice stocks so that the rice-eating population is not left to the mercy of the corrupt hoarders And in that context, I would like to know as to what has happened to state-trading in foodgrains of which so much had been said in the Bombay session of the All India Congress Committee and which forms so important a part and so important a plan of the socialistic programme of the Congress headed by Shrimati Indira Gandhi. I hope, Sir, Government owe an answer to this House on this very vital point because, in spite of the increased foodgrains production, the prices are also increasing and they are running a most on parallel lines which are going to meet nowhere.

Sir, the time being very short, I would like to dwell on another important aspect, which, according to me, is the only aspect of the Central Budget today and that is the devolution of finances to the States. I would request the hon. Finance Minister that he would be kind enough to furnish us with a statement of indices regarding Central investment in various States in the different sectors of our economy. The figures are jumbled up in the Demands for Grants in this Budget and unless one is adept enough, one cannot immediately find the various kinds of State Grants and Special Grants, etc., which are being given to the different States. My grievance is that as we proceed in our planning, we are proceeding not to-

wards social equality but towards social inequality and political inquity. Socialism does not only mean removal of disparity between a citizen and a citizen ; between a class of men and a class of men but also between States and States. There are under-developed States. There are developed States. There are some States for whom it is a perpetual and eternal problem as to how their non-Plan expenditure is to be met or even how to meet their administrative costs and there are States which generate sufficient surpluses for implementing their Plans. Therefore, Sir, in this context, any responsible Finance Minister has to review and examine this Central Budget, the central problem of which is, according to me, the devolution of Central Finances to the States.

When our Constitution Assembly was seized of this question, the issue was very limited.

The issue was devolution of Central Finances to the States according to Art. 280 of the Constitution, which had contemplated that there would be a Finance Commission a quinquinnial affairs, which would make awards from time to time to State Governments to meet their temporary liabilities.

When the Constituent Assembly had framed Art. 280 of the Constitution, the concept of the Plan had not come into existence. But, in the given context of today, it is the Plan and the Plan alone, which has transcended all the limited horizons of Art. 280. And, today, when we are confronted with a situation in with there are some States which have to depend upon the Central Loan for meeting their administrative expenditure, it will be for the Finance Minister, to tell us as to how those States are going to tackle with their problems of planned development and growth. And, if, in those States, anomosities grow, bitterness increase ; and pose a challenge to our nation, then, certainly, the responsibility squarely will rest on the shoulders of the Finance Minister.

Sir, in this context, I would like to remind you of one point. When Shri Vidya Charan Shukla was replying to the Debate on the Supplementary Demands he said that such States which want to give increased Dearness Allowance can look to the Centre for loans. I was almost tempted to ask him : How these loans are going to be serviced by the State Governments ? There are States like Orissa which have received huge loans from the Government of India. In servicing those loans, all the Grants and the Special Grants which they have been receiving, are being consumed. Therefore, the issue today is, as to what radical measures the Government of India can evolve, for the devolution of the finances to States like Orissa for the planned progress.

In this context, I find that the Special Grants which the Government of India had been giving are registering today diminishing return. We find that the non-plan Grants are on the dwindle and we would like to know from the hon. Finance Minister as to what it is that has necesssitated this situation.

For instance, in the Revised Budget, the non-Plan Grants were of the order of Rs. 141.83 crores. In 1971-72, it has been reduced to Rs. 136.87 crores. Whereas this reduction may not mean anything to richer and more resourceful States, certainly, it is going to mean a great hardship for States like Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan and Assam. There is another aspect. In the scheme of Central assistance to the States, 70 per cent component of this is loan 'and 30 per cent is grant. Variations are made in case of certain States like Assam, Nagaland, Jammu and Kashmir, etc., where the position is exactly reversed. The ratio or the component of loan there is 10 per cent whereas the grant is 90 per cent. If a rational classification is made, I do not see why any difference should be made in case of States like Orissa. If Assam can get 10 per cent loan and 90 per cent grant, certainly it is for the Government of India to give an answer as to why similarly placed, and underdeveloped States, in Similar situations, should not get that same consideration. I do not wish to join issue with the Government of India at this moment on this point, because the subject requires more detailed examination. But at this stage, I would only make a humble plea to the hon. Finance Minister that he should see that more redical measures are evolved so that under-developed States do not suffer from any handicap and do not recede to the backwaters of stagnation.

With these words, I commend the budget for the consideration of the House.

श्री शिव नाथ सिंह (झुंझुनु) : सभापति महोदय, हमारे वित्त मन्त्री जी ने आमदनी और खर्चे का ब्यौरा पेश करने हुए घोषणा की है कि कोई नया टैक्स नहीं लग या जा रहा है। इसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन जिस बजट में कोई नया टैक्स लगाया न गया हो, वह सही बजट है, इस बात को मानने के लिए मैं तैयार नही हूं। हमारा बजट हो या किसी भी देश का बजट हो वह उस देश के आर्थिक कार्यक्रम का एक संकेत करता है। हमारा देश किस आर्थिक प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ना चाहता है और किधर जाना चाहता है, इसका संकेत इस बजट में होना चाहिए था। वित्त मन्त्री जी ने एक दो बाते इस मे रखी है। एक बात तो यह है कि उन्होने इस में पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया है बेरोजगार लोगो को रोजगार देने के लिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम जनता के सामने आर्थिक प्रोग्राम को लेकर गए थे और जनता ने रेसपौंड किया है और हमारे ऊपर उसको लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी है। हम यह कह कर सन्तोष नहीं कर सकते हैं कि जनता के लिए हमने पचास करोड़ रुपया रख दिया है और कोई टैक्स नही लगाया है। यह प्रोग्राम हमने जनता को नही दिया है। जो विश्वास जनता ने हमारे ऊपर किया है और जो जिम्मेदारी हम पर सौंपी है उस विश्वास और उस जनता की भावनाओं को पूरा करने वाला यह बजट है, ऐसा कम से कम मैं तो नही मान सकता हूं और ऐसा कहने के लिए वित्त मन्त्री जी से माफी भी चाहता हूं। हम चाहते थे कि आर्थिक विषमता मिले, गरीबों का कुछ उद्धार हो, उसके वास्ते कमाई के साधन बढ़ेंगे, जो अमीर लोग हैं उनको कुछ नीचे लाया जाएगा। हमारे सामने दो खतरे हैं। एक तो साम्यवाद की तरफ से है। लेकिन साम्यवाद से भी ज्यादा बड़ा जो खतरा है वह पूंजीवाद से है। पिछले आम चुनाव में और पिछले ही नहीं उससे पहले के आम चुनावों में पूंजीवादियों ने हमारे देश को कहां से कहां चलवाना चाहा, पूंजीवादियों ने राज्य को किस तरह से पनपाना चाहा, इस को आप देखें। पूंजीपतियों की तादाद आजादी के बाद के कितने गुना बढ़ चुकी है, इसको भी आपको देखना चाहिए। पिछले बीस पच्चीस साल मे उन्होने शासन से सारे फायदे उठाए है। हमारी सरकार उन पर कन्ट्रोल नही कर सकी है। उसका यह नतीजा है कि पूंजीवाद सरकार *के सामने और कांग्रेस के सामने एक चैलेंस बन* कर आया है। उनका एक गिरोह बन गया है और गिरोह बना कर अपने पैसे के बलबूते पर वे देश पर शासन करना चाहते है। जनता की जो भावनायें थी और जो इसको बरदाश्त नही कर सकती थी, उनको देखते हुए जनता ने इस का सजीदगी के साथ उत्तर दिया है। जनता जो खतरे इसमे निहित थे, उनको भी समझती थी। इस वास्ते यह जो बजट है यह इस प्रकार का होना चाहिये था कि एक तरफ तो यह साम्यवाद के खतरे को मिटाने मे सहायक होता और दूसरी तरफ पूंजीवाद के खतरे को मिटाने मे सहायक होता।

हम देखते हैं कि आज देश मे इंडस्ट्री बढ़ी है, उद्योग धन्धे बढ़ रहे है। लेकिन उनका जो मुनाफा है वह कहा जाता है ? जो मजदूर उनमे काम करते हैं और जो 16-16 और 18-18 घन्टे काम करते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि इस बजट के द्वारा उनको सही उसका मुनाफा मिल सकेगा ? क्या उनको सही मजदूरी आप दिला सकेंगे ? इस ओर भी बजट में कोई संकेत नही है।

हम यह भी देखते हैं कि साम्यवादियो का बंगाल में चुनावों के पहले कितना जोर था, मार्क्सवादियों का कितना जोर था। लेकिन हम आर्थिक नीतियां लेकर, आर्थिक प्रोग्राम लेकर चुनाव में उतरे। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने वह प्रोग्राम दिया है और उस प्रोग्राम के बलबूते पर आज कांग्रेस को यहां कितना बहुमत मिला, इसको भी आप सामने

हैं। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि यदि हम देश को सही आर्थिक कार्यक्रम देंगे तो जनता हमारे साथ आएगी। लेकिन प्रश्न है कि क्या सही आर्थिक कार्यक्रम हम इसमें दे सके हैं? क्या इस बजट से जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हम कर पाए है? मैं समझता हूं कि नहीं कर पाये है।

देश में एक भावना फैली हुई है कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो रहा है। यह रेवोल्यूशन इनिशियल स्टेज पर है। जिस साल वर्षा अच्छी हो जाती है उस साल फसल अच्छी हो जाती है और हम मान बैठते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया है। लेकिन यह सही नही है। जिस साल वर्षा कम हो जाती है और सिंचाई के साधन नही होते है उस साल हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन खत्म हो जाता है। इस वास्ते इससे हमे सतोष नही कर लेना चाहिये और खेती के साधन मुहैया करने चाहिये और इसका प्रावधान बजट में होना चाहिये था। जिन लोगों के पास जमीन नही है, उसके लिए जमीन का प्रबन्ध होना चाहिए। जिनके पास जमीन है लेकिन बिजली नहीं है, उनके लिए बिजली का प्रावधान करना चाहिए। छोटे छोटे बंद हमको बनाने चाहिये, बड़े बड़े बांध बनाने चाहिये, बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाओं को हाथ में लेना चाहिए। राजस्थान नहर का भी एक सवाल है। कितने ही सालों से वह बनती आ रही है। कितने ही सालों से हम उसके लिए तरस रहे है। वह इतना बड़ा प्राजेक्ट है कि सेंटर जब तक उसको अपने हाथ में नही लेगा तब तक वह पूरा नहीं हो सकेगा। एडीक्वेट फंड्स यदि आप नहीं देंगे तो वह प्राजेक्ट पूरा नहीं हो सकेगा। इन सब चीजों के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए था। जब तक इस तरह की चीजों का प्रावधान नहीं होता है तब तक सच्चा समाजवाद हम जनता को नहीं दे सकेंगे, सच्ची तस्वीर जनता के सामने पेश नहीं कर सकेंगे।

जो भूखा पेट है, उसको खाने के लिए रोटी चाहिए। जिस के पास दो हाथ हैं और जो मजदूरी कर सकता है, वह भीख मांगना नहीं चाहता है। वे अपने दो हाथों से काम करना चाहते हैं। क्या आपने बजट में ऐसा प्रावधान जोड़ा है जिससे जो मजदूरी करना चाहे, उसको मजदूरी मिल जाए? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि जो आदमी काम करना चाहेगा, उसको काम मिल जायेगा। इस गम्भीर समस्यों के लिए पचास करोड़ रुपये की राशि बहुत कम है। इसके अतिरिक्त मैं इसको अच्छा नही समझता हूं कि रुपये के बल-बूते पर लोगों को एम्पलायमेंट दी जाये। हम चाहते हैं कि लोगों को काम के साधन जुटाये जायें, ताकि उन की अनएम्पलायमेंट खत्म हो सके। मैं वित्त मन्त्री से निवेदन करूंगा कि वह अगले बजट में इस बात का ध्यान रखें कि जनता की भावनायें क्या हैं और वह क्या चाहती है।

यह ठीक है कि हमारे देश में इंडस्ट्रीज बढ़ी हैं, लेकिन उनके मुनाफे पर रोक लगाने की आवश्यकता है। वित्त मन्त्री ने कोई टैक्स नहीं लगाया है, इस का मैं स्वागत करता हूं उस जनता की तरफ से, जो पहले से ही टैक्सों से दबी हुई है। लेकिन जिनके पास बहुत पैसा हैं जो इंडस्ट्रीज से बहुत पैसा कमाते हैं जो सौ में से नब्बे रुपये अपने पाकेट में रखते हैं और ब्लैक मनी के बल पर कई अवांछनीय धन्धे करते है तथा हमारी राजनीति में विष फैलाना चाहते है उन पर सरकार टैक्स लगाए और उनका धन ले कर लेबरर्ज को दे ताकि उन की स्थिति अच्छी हो। जितने भी बड़े बड़े उद्योग है, उनको सरकारी क्षेत्र मे किया जाए। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक पूंजीवाद बढ़ता रहेगा और हमारे देश के लिए सब से बड़ा खतरा बना रहेगा।

जैसा कि मैंने कहा है, टैक्स न लगाने के लिए मैं वित्त मन्त्री का स्वागत करता हूं, लेकिन वास्तव में मैं उनका स्वागत उस रोज

[श्री शिव नाथ सिंह]

कहूंगा, जब वह यह घोषणा करेंगे कि हम राजा-महाराजाओं के प्रिवी-पर्स बिना किसी मुआवजे के खत्म करेंगे। यह संस्था बहुत पुरानी पड़ चुकी है और आज उसकी जरूरत नहीं है। हम प्रिवी पर्स को खत्म करने का सिद्धान्त मान चुके हैं, लेकिन हमारे मन में आशंका है कि प्रिवी पर्स खत्म तो होंगे, किन्तु उनके लिए मुआवजा दिया जायेगा। वित्त मन्त्री और भारत सरकार इस बारे में निर्णय लेकर घोषणा करें।

जैसा कि हमने लोगों से वादा किया है, शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाई जाये। जिनके पास अतिरिक्त सम्पत्ति है, वह बिना मुआवजा दिये ले ली जाये। अगर इसके लिए कान्स्टीट्यूशन में कोई एमेंडमेंट की जायेगी, तो हम और पूरी जनता उसका स्वागत करेंगे। जिन लोगों के पास धन है, अगर मुआवजा देकर उन को और धनी बनाया जायेगा, तो उससे देश को कोई फायदा नहीं होगा और हमने जनता के सामने जो वादा किया है वह पूरा नहीं हो पायेगा।

अगर हम जनता की भावनाओं को दृष्टि में रखकर काम करेंगे, तो साम्यवाद का खतरा मिटेगा। हमने पश्चिमी बंगाल और केरल में साम्यवाद का खतरा देख लिया है। चूंकि युवकों के सामने कोई आर्थिक प्रोग्राम नहीं था, उनके पास कोई काम नहीं था, इसलिए वे साम्यवादी और नक्सलवादी हो रहे थे। अब उनके सामने निश्चित आर्थिक कार्यक्रम रखे गये और उनको एक दिशा मिल गई, तो वे सही रास्ते पर आ गये। लेकिन अगर इसी तरह के बजट बनते गये और जनता के सामने किये गये वादों को पूरा नहीं किया गया, तो आगे चलकर हमें अधिक बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। इसलिये सरकार को ऐसी नीति पर चलना चाहिए, जिससे युवकों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। जब तक बजट में यह प्रावधान नहीं होगा कि जिस के पास आज सम्पत्ति है, वह और अधिक सम्पत्ति अर्जित न कर सके, तब तक वह सही बजट नहीं समझा जायेगा।

मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय आने वाले बजट में इन बातों का समावेश करेंगे और जनता की सही आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Shri Sarjoo Pandey—he will start tomorrow.

The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

17.59 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, March 26, 1971/Chaitra 5, 1893 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.